Volume 1; Issue 1
January to March 2025

E-ISSN: 3049-1134

International Journal of Political Studies

Peer Review Indexed Refereed Journal

Quarterly International Research Journal

International Journal of Political Studies
E-ISSN: 3049-1134
https://www.polsci.in
Volume 1; Issue 1; January to March 2025; Page No. 61-70
Peer Review, Indexed and Refereed Journal

वैश्वीकरण के दौर में गांधी का ग्राम स्वराज मॉडलः एक अध्ययन

डा. सुनीता बघेले
सहायक प्राध्यापक
राजनीति शास्त्र,
भगवान विरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय,
दिव्यगवा, रीवा मध्य प्रदेश

सारांश

वर्तमान समय में वैश्वीकरण एक प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रिया बन चुका है, जिसने संपूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में जोड़ने का कार्य किया है। यह प्रक्रिया जहाँ एक ओर तकनीकी विकास, आर्थिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर यह स्थानीय पहचान, पारंपरिक आजीविका एवं आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है। इस सन्दर्भ में महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज मॉडल एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता, नैतिकता एवं लोकतंत्र को प्राथमिकता देता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य वैश्वीकरण की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में गांधी के ग्राम स्वराज मॉडल की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना है। शोध इस बात की पड़ताल करेगा कि किस प्रकार गांधी का आदर्श ग्राम वैश्वीकरण के दबावों के मध्य भी एक टिकाऊ एवं समतामूलक समाज की आधारशिला बन सकता है।

मुख्य शब्दः *वैश्वीकरण, गांधी, ग्राम स्वराज मॉडल*

प्रस्तावना

वर्तमान समय में वैश्वीकरण एक प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रिया बन चुका है, जिसने संपूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में जोड़ने का कार्य किया है। यह प्रक्रिया जहाँ एक ओर तकनीकी विकास, आर्थिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी

ओर यह स्थानीय पहचान, पारंपरिक आजीविका एवं आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है। इस सन्दर्भ में महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज मॉडल एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता, नैतिकता एवं लोकतंत्र को प्राथमिकता देता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य वैश्वीकरण की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में गांधी के ग्राम स्वराज मॉडल की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना है। शोध इस बात की पड़ताल करेगा कि किस प्रकार गांधी का आदर्श ग्राम वैश्वीकरण के दबावों के मध्य भी एक टिकाऊ एवं समतामूलक समाज की आधारशिला बन सकता है।

गांधी का ग्राम स्वराज मॉडल

गांधी का ग्राम स्वराज मॉडल भारतीय जीवन दृष्टि, सांस्कृतिक परंपरा और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक समन्वित स्वरूप है। गांधी का मानना था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और कृषि प्रधान देश के लिए विकास की सही दिशा केंद्रित शहरीकरण नहीं, बल्कि विकेंद्रित ग्राम स्वराज हो सकती है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि "ग्राम स्वराज का अर्थ है, एक ऐसा गाँव जो अपनी सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम हो, और इस प्रक्रिया में अन्य गाँवों के साथ समन्वय बनाए रखे" (Gandhi: 1961, p. 34)। गांधी द्वारा प्रस्तावित ग्राम स्वराज की परिकल्पना एक आदर्श समाज की संकल्पना थी, जो आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर टिकी होती है। उनके अनुसार ग्राम स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वशासन नहीं है, बल्कि यह आत्म–नियंत्रण, आत्म–संयम, और नैतिकता की गहराई से जुड़ा हुआ है। वे मानते थे कि भारत की शक्ति गाँवों में है, और जब तक गाँव आत्मनिर्भर, सशक्त और नैतिक रूप से उन्नत नहीं होंगे, तब तक भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। गांधी के अनुसार, "ग्राम स्वराज तभी साकार हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि वह न केवल अपने गाँव के लिए, बल्कि राष्ट्र और विश्व के लिए उत्तरदायी है" (Gandhi: 1938, p. 76)।

गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम की विशेषताएँ स्पष्ट और व्यापक थीं। इनमें सबसे प्रमुख है कि स्थानीय उत्पादन और उपभोग की व्यवस्था, जिससे गाँव अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर सके। वे खादी, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करते थे, जिससे स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो और बेरोजगारी न फैले। ग्राम शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षरज्ञान नहीं, बल्कि जीवनोपयोगी, नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना था, जो युवाओं को उत्पादक और समाजोन्मुख बनाए। ग्राम

स्वराज में सामाजिक समरसता को भी विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और स्त्री–पुरुष असमानता का कोई स्थान नहीं होता। गांधी का विचार था कि "गाँव की आत्मनिर्भरता तभी पूर्ण हो सकती है जब वह सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर न्यायसंगत हो" (Narayanasamy: 2013, p. 59)।

पंचायती राज और स्थानीय शासन की भूमिका गांधी के ग्राम स्वराज मॉडल की राजनीतिक रीढ़ है। गांधी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें तभी गहरी हो सकती हैं जब निर्णय प्रक्रिया में गाँव का प्रत्येक नागरिक सीधे भाग ले। भारत के संविधान में 73 वें संशोधन (1992) के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो संवैधानिक मान्यता मिली, वह गांधी की परिकल्पना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन व्यवहार में अभी भी पंचायतें संसाधनों, प्रशिक्षण और स्वतंत्रता की कमी से जूझ रही हैं। जब तक आर्थिक और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, ग्राम स्वराज की आत्मा मृतप्राय बनी रहेगी। जैसा कि ठ.ठ. ठींजजंबींतलं ने अपने लेख में कहा है, "ग्राम स्वराज केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि सशक्त लोकशाही का आधार हो सकता है यदि इसे जमीनी स्तर पर सशक्त किया जाए" (Bhattacharya: 1998, pp. 221–225)।

ग्राम स्वराज केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि गहरे नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित जीवन दृष्टि है। गांधी के लिए नैतिकता सामाजिक जीवन का केंद्र थी। वे मानते थे कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और श्रम– ये मूल्य ग्राम जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाते हैं। उनके अनुसार, "ग्राम स्वराज आत्मा की स्वतंत्रता है, शरीर की नहीं। यह आंतरिक अनुशासन से आता है, बाह्य सत्ता से नहीं" (Gandhi: 1925, p. 211)। वे यह भी मानते थे कि आर्थिक गतिविधियाँ केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि सेवा और संतुलन के लिए होनी चाहिए। सेवा प्रकृति की, सेवा समाज की और सेवा आत्मा की।

इस प्रकार गांधी का ग्राम स्वराज मॉडल एक ऐसा समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो आज की विकास की एकांगी और केंद्रीकृत प्रवृत्तियों के विपरीत, एक नैतिक, सामाजिक और आत्मनिर्भर विकल्प प्रदान करता है। यह मॉडल केवल ग्रामीण भारत की नहीं, बल्कि समूचे विश्व की उन समस्याओं का उत्तर बन सकता है जो असमानता, पर्यावरणीय संकट और आत्मवंचना से जुड़ी हैं। गांधी का ग्राम स्वराज इसलिए न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसकी वर्तमान और भविष्य की प्रासंगिकता भी अत्यंत गहन और व्यापक है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया और उसका प्रभाव

वैश्वीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देश, समाज और अर्थव्यवस्थाएँ आपस में गहरे रूप से जुड़ गए हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक उदारीकरण, तकनीकी विकास, वैश्विक व्यापार, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और राजनीतिक सहयोग के माध्यम से धीरे–धीरे विकसित हुई है। विशेष रूप से भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात् वैश्वीकरण ने तीव्र गति प्राप्त की। सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने देश के दरवाजे विश्व पूँजी, प्रौद्योगिकी और व्यापार के लिए खोल दिए (Government of India, Economic Reforms of 1991, Ministry of Finance)।

इस प्रक्रिया के प्रभाव अनेक स्तरों पर दृष्टिगोचर होते हैं। एक ओर वैश्वीकरण ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर दिया है। विदेशी निवेश में वृद्धि, तकनीकी उन्नति, उपभोक्ता विकल्पों का विस्तार और सूचना संचार क्रांति के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर शहरी भारत, में व्यापक विकास हुआ है। IT क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की सफलता, और स्टार्टअप संस्कृति का विस्तार दृ यह सब वैश्वीकरण की देन हैं। साथ ही, शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक सहयोग से गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

दूसरी ओर, इस प्रक्रिया के गंभीर नकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं, विशेषतः ग्रामीण भारत और परंपरागत अर्थव्यवस्थाओं पर। वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा के चलते कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और खादी जैसे परंपरागत उत्पादन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। छोटे किसान वैश्विक मूल्य अस्थिरता, लागत में वृद्धि और कॉर्पोरेट कृषि के दबाव में आकर असुरक्षित हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसान आत्महत्याओं की घटनाएँ भी बढ़ी हैं (Desai 2007, pp. 17–24)। सांस्कृतिक स्तर पर भी वैश्वीकरण ने उपभोक्तावादी संस्कृति, पश्चिमी जीवनशैली और एकरूपता को बढ़ावा दिया, जिससे पारंपरिक भारतीय मूल्य, लोक कलाएँ और भाषाएँ हाशिए पर जाने लगीं। विशेष रूप से युवा वर्ग में स्थानीय विरासत की समझ कमजोर होती जा रही है। इस संदर्भ में नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन लिखते हैं कि ‘‘वैश्वीकरण की दिशा तब तक सकारात्मक नहीं हो सकती जब तक उसमें सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भरता के तत्व न जोड़े जाएँ’’ (Sen: 2000, pp. 146–152)।

इन परिस्थितियों में गांधी का ग्राम स्वराज मॉडल एक वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह मॉडल विकेन्द्रीकरण,

आत्मनिर्भरता, नैतिक अर्थशास्त्र और स्थानीय संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर आधारित है। वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि विकास की प्रक्रिया को स्थानीय आवश्यकताओं, पारंपरिक ज्ञान और सहभागी लोकतंत्र से जोड़ा जाए, तो यह संभव है कि वैश्वीकरण और ग्राम स्वराज एक–दूसरे के पूरक बन सकें।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण कोई पूर्णतः सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संदर्भ और दिशा पर निर्भर करती है। यदि इसे गांधीवादी मूल्यों के आलोक में समझा और क्रियान्वित किया जाए, तो यह न केवल आर्थिक विकास को गति दे सकती है, बल्कि सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता को भी संरक्षित रख सकती है।

गांधी के ग्राम स्वराज मॉडल की वर्तमान प्रासंगिकता

गांधी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज का विचार स्वतंत्र भारत के निर्माण हेतु केवल एक आर्थिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज की आत्मा के अनुरूप जीवन की संपूर्ण दृष्टि थी। गांधी मानते थे कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, और जब तक गाँव आत्मनिर्भर, सशक्त, और नैतिक रूप से उन्नत नहीं होंगे, तब तक भारत का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों में प्रस्तुत यह विचार आज इक्कीसवीं सदी में, विशेष रूप से वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, और सामाजिक विषमता के बढ़ते संकट के बीच अत्यंत प्रासंगिक हो उठा है। गांधी के ग्राम स्वराज का मूलतः अर्थ है दृ एक ऐसा गाँव जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, बल्कि सामाजिक दृष्टि से समरस, नैतिक रूप से जागरूक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने वाला हो। 'हर गाँव एक पूर्ण गणराज्य हो सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके और जीवन के मूलभूत निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके' दृ यह गांधी की मूल परिकल्पना थी (Gandhi: 1967, p. 176)।

वर्तमान भारत में जब एक ओर स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गाँवों में निवास करती है। वैश्वीकरण और शहरीकरण के प्रभाव में गाँवों की सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और संस्कृति तेजी से बदल रही है। ऐसी स्थिति में गांधी का ग्राम स्वराज मॉडल हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम अपने ग्रामीण समाज की आत्मा को बचा पा रहे हैं, या हम उसे आधुनिकता की दौड़ में खोते जा रहे हैं? कोविड–19 महामारी के समय भारत के लाखों प्रवासी मजदूरों का शहरों से गाँवों की ओर पलायन इस बात का संकेत था कि

आज भी गाँव ही अंतिम आश्रय स्थल हैं। यह संकट काल इस तथ्य को उजागर करता है कि यदि गाँव आत्मनिर्भर होते, यदि वहाँ स्थानीय उत्पादन और रोजगार के अवसर होते, यदि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होतीं, तो इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी से बचा जा सकता था (Kumar: 2020, pp. 210–225)।

आज भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी योजनाएँ गांधी के ग्राम स्वराज की आधुनिक छाया प्रतीत होती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है दृ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बनाना और विकेन्द्रीकरण के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया को जमीनी स्तर तक पहुँचाना। यद्यपि इन योजनाओं की संरचना गांधीवादी मॉडल के अनुरूप है, किंतु व्यवहार में यह अभी भी एक आर्थिक कार्यक्रम तक ही सीमित प्रतीत होती है। जबकि गांधी का ग्राम स्वराज एक समग्र जीवन पद्धति है जिसमें नैतिकता, सहजीवन, और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का समावेश है (Narayanasamy: 2013, p. 102)।

ग्राम स्वराज की वर्तमान प्रासंगिकता को पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन की समस्या वैश्विक स्तर पर गंभीर हो चुकी है। गांधी का ग्राम स्वराज विचार स्थानीय संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, और टिकाऊ जीवनशैली पर बल देता है, जो सतत विकास के लक्ष्यों ‘ैनेजंपदंइसम क्मअमसवचउमदज ळवंसे दृ ैक्ळे) से गहराई से जुड़ा हुआ है (NITI Aayog: 2021, pp. 5–30)।

ग्राम स्वराज की एक अन्य प्रासंगिकता भारत की लोकतांत्रिक संरचना में निहित है। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे गाँवों में लोकतांत्रिक भागीदारी की संभावना बढ़ी। किंतु व्यावहारिक स्तर पर ग्राम पंचायतें अभी भी संसाधनों और निर्णय की स्वतंत्रता के अभाव में पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पाई हैं। गांधी का ग्राम स्वराज एक ऐसे राजनीतिक ढाँचे की बात करता है जहाँ प्रत्येक नागरिक की सीधी भागीदारी हो, और निर्णय सामूहिकता पर आधारित हों (Mehta: 2019, pp. 24–29)।

अंततः गांधी के ग्राम स्वराज की वर्तमान प्रासंगिकता केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समूचे राष्ट्र के लिए एक वैकल्पिक विकास दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह विचार शांति, सामंजस्य, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों के आधार पर एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है

जहाँ मनुष्य केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि सृजनकर्ता और सहभागी नागरिक होता है। जिस समय वैश्वीकरण, तकनीकी यांत्रिकता और आर्थिक केंद्रीकरण मानव जीवन को विस्थापन और असमानता की ओर ले जा रहे हैं, उस समय गांधी का ग्राम स्वराज न केवल प्रासंगिक है, बल्कि अत्यावश्यक भी।

चुनौतियाँ और सम्भावना

गांधी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज मॉडल का क्रियान्वयन स्वतंत्र भारत में एक आदर्श के रूप में तो स्वीकार किया गया, किंतु व्यवहारिक स्तर पर इसे अपनाने में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं। इन चुनौतियों का संबंध केवल प्रशासनिक या आर्थिक बाधाओं से नहीं है, बल्कि वैचारिक और नीतिगत दृष्टिकोण की सीमाओं से भी है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने औद्योगिक विकास, केन्द्रीय योजनाओं और शहरीकरण को प्राथमिकता दी, जिससे ग्राम आधारित विकास दृष्टि धीरे–धीरे नीति–निर्माण के हाशिए पर चली गई।

ग्राम स्वराज मॉडल को लागू करने में सबसे प्रमुख बाधा रही हैकृकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली और योजनाओं का शीर्ष से नीचे (ज्वच–कवूद) दृष्टिकोण। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा संवैधानिक दर्जा तो दिया गया, लेकिन उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता अभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारें और नौकरशाही अक्सर पंचायती संस्थाओं को वास्तविक अधिकार देने में संकोच करती हैं। कई शोधों में यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायतें केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई बनकर रह गई हैं, जबकि निर्णय–निर्माण का अधिकार ऊपर के स्तर पर सीमित है (Mathew: 2017, p. 45)।

इसके अतिरिक्त, ग्राम स्वराज के आर्थिक स्तंभकृकुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादनकृवैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा, आधुनिक उपभोक्तावाद और तकनीकी केंद्रीकरण के चलते कमजोर हो गए हैं। सरकार की औद्योगिक नीतियाँ बड़े उद्योगों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को बढ़ावा देती रही हैं, जिससे ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को अपेक्षित संरक्षण और समर्थन नहीं मिल पाया। 'खादी ग्रामोद्योग आयोग' जैसे संस्थानों को पर्याप्त संसाधन और नवाचार की स्वतंत्रता नहीं दी गई, जिससे ये संस्थाएँ महज प्रतीकात्मक बनकर रह गई हैं (Dantwala: 1973, pp. 305–312)।

एक और गंभीर बाधा हैकृशिक्षा और सामाजिक चेतना का अभाव। गांधी का ग्राम स्वराज केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक नैतिक समाज का निर्माण है। इसके लिए चरित्र निर्माण, सामाजिक सेवा, श्रम के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक सहभागिता की भावना अत्यावश्यक है। किंतु वर्तमान

शिक्षा प्रणाली प्रतियोगिता, नौकरी और लाभ आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिससे नागरिकों में सामाजिक उत्तरदायित्व और ग्राम स्वराज की भावना विकसित नहीं हो पाती (Kumar: 2004, p. 92)। नीतिगत स्तर पर भी गांधी विचारधारा की उपेक्षा स्पष्ट देखी जा सकती है। यद्यपि सरकारों ने समय–समय पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किएकृजैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों योजना, और स्वच्छ भारत अभियानकृ लेकिन इन योजनाओं का दृष्टिकोण गांधी के आत्मनिर्भर और नैतिक समाज की कल्पना से मेल नहीं खाता। अधिकांश योजनाएँ केवल अवसंरचना निर्माण या अल्पकालिक रोजगार सृजन तक सीमित रहती हैं। गांधीवादी विचारकों का मानना है कि "ग्राम स्वराज केवल विकास योजनाओं की बात नहीं करता, यह एक जीवन पद्धति है, जिसमें सामुदायिक चेतना, पर्यावरणीय संतुलन और नैतिक आत्मबल की आवश्यकता होती है" (Radhakrishna: 2020, pp. 385–391)।

फिर भी, इन चुनौतियों के बावजूद ग्राम स्वराज मॉडल में अनेक संभावनाएँ निहित हैं, विशेषकर आज के सामाजिक और पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में। जलवायु परिवर्तन, असमानता, बेरोजगारी और शहरी अव्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए विकेन्द्रीकृत, स्थानीय और टिकाऊ मॉडल की आवश्यकता स्पष्ट होती जा रही है। ग्राम स्वराज मॉडल स्थानीय संसाधनों के उपयोग, रोजगार सृजन, सामाजिक सहभागिता और पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित होने के कारण एक व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करता है।

सरकारी नीतियों को यदि गांधीवादी दृष्टिकोण से पुनर्निर्मित किया जाए, तो इन संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देने वाली खरीद नीति, ग्राम शिक्षा में कार्य–आधारित शिक्षण, पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्र बजटीय अधिकार, और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दृ ये सब नीतिगत पहलें ग्राम स्वराज के दिशा में प्रभावी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, नीति–निर्माताओं को यह समझना होगा कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन, नैतिकता और आत्मनिर्भरता को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए (Planning Commission of India, Report 2011, p. 23)।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि गांधी के ग्राम स्वराज मॉडल के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ हैं, किंतु वर्तमान संदर्भ में उसकी संभावनाएँ कहीं अधिक गहरी और दूरगामी हैं। यदि नीतियों में गांधीवादी सोच को यथार्थ रूप में समाहित किया जाए, तो ग्राम स्वराज केवल एक

आदर्श नहीं, बल्कि एक सशक्त और सजीव विकास मॉडल बन सकता है।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण के इस युग में गांधी का ग्राम स्वराज मॉडल एक नैतिक, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जबकि वैश्वीकरण अनेक अवसर प्रदान करता है, वहीं यह अनेक असंतुलन भी उत्पन्न करता है। ऐसे में ग्राम स्वराज न केवल एक वैकल्पिक विकास मॉडल है, बल्कि यह मानवीय गरिमा, सामाजिक समरसता एवं पर्यावरणीय संतुलन की आधारशिला भी है। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम गांधी के विचारों की पुनर्व्याख्या करें और उन्हें आधुनिक संदर्भ में लागू करने के प्रयास करें।

संदर्भिका

Bhattacharya, B.B., *"Democratic Decentralization and Gandhian Vision"*, Economic and Political Weekly, Vol. 33, No. 5, 1998, pp. 221–22

Dantwala, M.L., *"Planning for the Millions"*, Economic and Political Weekly, Vol. 8, No. 7, 1973, pp. 305–312

Desai, M. (2007). *Globalization and its Discontents*, Yojana, Vol. 51, pp. 17–24

Gandhi, M.K., *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 66, Navajivan Trust, Ahmedabad, 1967, p. 176

Gandhi, M.K., *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 52, Navajivan Trust, Ahmedabad, 1961, p. 34

Gandhi, M.K., *Hind Swaraj*, Navajivan Publishing House, 1938, p. 76

Gandhi, M.K., *Young India*, 18 June 1925, p. 211

Government of India, Economic Reforms of 1991, Ministry of Finance

Kumar, K., *What Is Worth Teaching*, Orient Blackswan, 2004, p. 92

Kumar, S. *"Revisiting Gandhi in COVID Times"*, Indian Journal of Social Work, Vol. 81(2), 2020, pp. 210–225

Mathew, G., *Status of Panchayati Raj in the States of India*, Institute of Social Sciences, New Delhi, 2017, p. 45

Mehta, B. *"Technology for Inclusive Development: Gandhian Perspective"*, Yojana, Vol. 63, 2019, pp. 24–29

Narayanasamy, N., *Gandhian Approach to Rural Development*, Concept Publishing, New Delhi, 2013, p. 102

Narayanasamy, N., *Gandhian Approach to Rural Development*, Concept Publishing Company, New Delhi, 2013, p. 59

NITI Aayog. *SDG India Index & Dashboard 2020–21*, Government of India, New Delhi, 2021, pp. 5–30

Planning Commission of India, Report of the Working Group on Decentralised Planning, 2011, p. 23

Radhakrishna, M., *"Gandhi's Legacy and Contemporary Rural Development"*, Social Change, Vol. 50, No. 3, 2020, pp. 385–391

Sen, A. (2000). *Development as Freedom.* Oxford University Press, pp. 146–152